(iii) प्रारम्भिक स्कूल अध्यापकों तथा प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ।

पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले विशेष रूप से लड़कियों के मामले से सम्बन्धित समस्या एक बहुत ही चिंता का विषय है जिसका उपयोगी रूप से हल ढूंढ़ निकालने के लिए अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जाने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं । राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से भिन्न-भिन्न कवरेज सहित मध्याह्न भोजन निःशुल्क वर्दियों की आपूर्ति में जैसे कुछ अन्य प्रेरणादायक कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा हिन्दी में आयोजित किया जाना

109. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रवेश-परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी उपलब्ध कराने का निर्णय, जैसाकि इन संस्थानों की परिषद द्वारा निर्णय किया गया है ; इस वर्ष से ही कार्यान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा ;

(ख) क्या इस प्रवेश-परीक्षा में प्रश्न पत्र, हिन्दी के अतिरिक्त संविधान में उल्लिखित अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाएंगे ; और

(ग) यदि हां; तो कब तक?

(ख) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी परिषद् के निर्णयानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों की व्यवस्था करने में हुए अनुभव के आधार पर अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए उपाय किये जायंगे । अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कौन से वर्ष से किया जायेगा ।

शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना

110. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को कोई विशेष प्रशिक्षण, देने का विचार रखती है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में, विशेषकर राज्य के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में भी शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार लाने के लिए दस-दिवसीय अनुस्थापन शिविर के माध्यम से सेवा कालीन शिक्षा का एक कार्यक्रम वर्ष 1986 से कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1986–90 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13.47 लाख शिक्षक प्रशिक्षित किए गए थे । वर्ष 1989–90 के दौरान लगभग 4.40 लाख शिक्षकों को शामिल किए जाने की संभावना है ।

शिक्षक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अभी तक 217 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (जि०शि० प्र०सं०) को केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है । इन संस्थानों का मुख्य कार्य प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों तथा प्रौढ़ और गैर-औपचारिक शिक्षा पर कार्य कर रहे कार्मिकों को पूर्व-सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षा प्रदान

करना है । इसके अतिरिक्त, 32 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी गई है जिससे कि उन्हें मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के योग्य बनाया जा सके ।

(ग) वर्ष 1986-89 के दौरान मध्य प्रदेश के लगभग 84,000 शिक्षकों को दस-दिवसीय अनुस्थापन शिविरों के जरिए शामिल किया गया है । राज्य के 30 जिलों के लिए जि0 शि0 प्र0 संस्थान संस्वीकृत किए गए जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक की जनजातीय जनसंख्या वाले निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है :—

झाबुआ, बेतुल, रतलाम, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, मण्डला, शाहडोल, सरगुजा, पश्चिम-निमाड़ सिद्धी और सिओनी ।

देश में इंजीनियरिंग कालेज

111. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थित प्राइवेट और सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या और उनकी क्षमता के बारे में कोई आंकलन किया गया है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि प्रति वर्ष इन कालेजों में प्रशिक्षित होने वाले इंजीनियरों की संख्या देश की आवश्यकता के अनुरूप है अथवा नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में प्रशिक्षित इंजीनियरों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और कुछ राज्यों में आवश्यकता से कम है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में कोई नया इंजीनियरी कालेज खोलने पर विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मैनन) : (क) से (घ) उत्तीर्ण इंजीनियरी स्नातकों के राज्यवार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा निजी तथा राजकीय इंजीनियरी कालेजों—दोनों के संबंध में नई दिल्ली स्थित अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संसूचना प्रणाली के कार्यक्रम के अंतर्गत इन स्नातकों को खपाने के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं । इन आंकड़ों की तुलना से संबंधित आंकड़े रोजगार मार्किट में इनकी मांग को स्पष्ट करने तथा विषयक्षेत्रों में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े भी तैयार किए जाते हैं । अनुप्रयुक्त जनशक्ति संस्थान में ब्यौरेवार दस्तावेज प्रकाशित किए जाते हैं और उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ।

इंजीनियरी स्नातकों के अधिक अथवा कमी से संबंधित अनुबंध सभी राज्यों में समान नहीं होते हैं । प्रत्येक राज्य में समान वर्ग के इंजीनियरों में कुछ बेरोजगारी विद्यमान होती है जबकि अन्य वर्गों के संबंध में ऐसा नहीं होता ।

अतः इस प्रकार एकत्रित आंकड़े राज्य आयोजन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और आयोजना आयोग के विचारार्थ वे राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास की योजना तैयार कर सकें ।

(ङ) इस समय मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नया इंजीनियरी कालेज को आरंभ करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

Manufacture of light combat aircraft

112. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) what is the latest position regarding manufacture of Light Combat Aircraft;